2018 में वाणिज्यिक न्यायालयों में मामले

वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर)			
राज्य का नाम	31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान दायर किए गए नए वाणिज्यिक मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गए वाणिज्यिक मामलों की संख्या	लंबित वाणिज्यिक मामलों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
असम	शून्य	शून्य	शून्य
बिहार	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0
छत्तीसगढ	--	--	--
दादर और नगर हवेली	--	--	--
दमन और दीव	--	--	--
गोवा	--	--	--
गुजरात	3	3	0
हरियाणा	60	3	58
हिमाचल प्रदेश	--	--	--
जम्मू और कश्मीर	1	शून्य	1
झारखंड	0	0	0
कर्नाटक	--	--	--
मध्य प्रदेश	22	6	83
महाराष्ट्र	--	--	--
उड़ीसा	--	--	--
पंजाब	25	19	353
राजस्थान	--	--	--
सिक्किम	राज्य में कोई वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर) नहीं हैं।		
तमिलनाडु	शून्य		
तेलंगाना	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तर प्रदेश	--	--	--
उत्तराखंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दिल्ली	उच्च न्यायालय ने जानकारी नहीं दी।		
पश्चिम बंगाल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मेघालय	कोई वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।		
केरल	शून्य	शून्य	शून्य

2019 में वाणिज्यिक न्यायालयों में मामले

वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर)			
राज्य का नाम	31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान दायर किए गए नए वाणिज्यिक मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गए वाणिज्यिक मामलों की संख्या	लंबित वाणिज्यिक मामलों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
असम	शून्य	शून्य	शून्य
बिहार	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0
छत्तीसगढ	--	--	--
दादर और नगर हवेली	--	--	--
दमन और दीव	--	--	--
गोवा	--	--	--
गुजरात	4	1	3
हरियाणा	57	4	58
हिमाचल प्रदेश	--	--	--
जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
झारखंड	0	0	0
कर्नाटक	--	--	--
मध्य प्रदेश	35	25	93
महाराष्ट्र	13	4	9
उड़ीसा	--	--	--
पंजाब	147	39	185
राजस्थान	--	--	--
सिक्किम	राज्य में कोई वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर) नहीं हैं।		
तमिलनाडु	शून्य		
तेलंगाना	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तर प्रदेश	--	--	--
उत्तराखंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दिल्ली	उच्च न्यायालय ने जानकारी नहीं दी।		
पश्चिम बंगाल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मेघालय	कोई वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।		
केरल	शून्य	शून्य	शून्य

2020 में वाणिज्यिक न्यायालयों में मामले

वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर)			
राज्य का नाम	31 दिसंबर, 2020 तक वर्ष के दौरान दायर किए गए नए वाणिज्यिक मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गए वाणिज्यिक मामलों की संख्या	लंबित वाणिज्यिक मामलों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
असम	शून्य	शून्य	शून्य
बिहार	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0
छत्तीसगढ	--	--	--
दादर और नगर हवेली	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0
गोवा	57	52	5
गुजरात	13	5	1 1
हरियाणा	40	3	42
हिमाचल प्रदेश	--	--	--
जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
झारखंड	0	0	0
कर्नाटक	--	--	--
मध्य प्रदेश	36	22	107
महाराष्ट्र	4	3	10
उड़ीसा	--	--	--
पंजाब	41	7	203
राजस्थान	--	--	--
सिक्किम	राज्य में कोई वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर) नहीं हैं।		
तमिलनाडु	शून्य		
तेलंगाना	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तर प्रदेश	--	--	--
उत्तराखंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दिल्ली	उच्च न्यायालय ने जानकारी नहीं दी।		
पश्चिम बंगाल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मेघालय	कोई वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।		
केरल	1	1	0

2021 में 30.06.2021 तक वाणिज्यिक न्यायालयों में मामले

वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर)			
राज्य का नाम	वर्ष के दौरान दायर किए गए नए वाणिज्यिक मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गए वाणिज्यिक मामलों की संख्या	लंबित वाणिज्यिक मामलों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
असम	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़ (31.03.2021 तक)	0	0	0
छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़ राज्य में वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर) की स्थापना नहीं की गई है।		
दादर और नगर हवेली	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0
गोवा	1	5	1
गुजरात	13	8	16
हरियाणा (31.03.2021 तक)	16	8	126
हिमाचल प्रदेश	--	--	--
जम्मू और कश्मीर (31.03.2021 तक)	शून्य	शून्य	शून्य
झारखंड	0	0	0
कर्नाटक (31.03.2021 तक)	--	--	--
मध्य प्रदेश (31.03.2021 तक)	12	4	115
महाराष्ट्र	3	1	12
उड़ीसा	--	--	--
बिहार (31.03.2021 तक)	0	0	0
पंजाब (31.03.2021 तक)	29	9	223
राजस्थान	--	--	--
सिक्किम	राज्य में कोई वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर) नहीं हैं।		
तमिलनाडु	शून्य		
तेलंगाना (31.03.2021 तक)	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तर प्रदेश	--	--	--
उत्तराखंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दिल्ली	उच्च न्यायालय ने जानकारी नहीं दी।		

पश्चिम बंगाल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मेघालय	कोई वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।		
केरल	10	2	8